टाइम्स ऑफ़ पीडिया

ٹائمس آف پیڈیا

TIMES OF PEDIA

NEW DELHI Page 12 Price ₹ 3.00

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इंसाफ़ की डगर पर

www.timesofpedia.com

WEEKLY HINDI ENGLISH URDU

WED 02 MAR - TUE 08 MAR 2016 | VOL. 4 Issue 18 | RNI No. DELMUL/2012/47011 | P.Reg. No. DL(S) - 01/3431/2013 - 15

संपादकीय

देश मुरीद कन्हैया का? या मुराद मांग रहा उसके जीवन की?

झूठ कहूँ तो लफ्जों का दम घुटता है।
सच बोलूं तो लोग खफा होजाते हैं।।

दांत में दर्द, डॉक्टर,पैर टूट गया, डॉक्टर इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई तकलीफ है डॉक्टर इलाज करेगा और लोग ठीक भी होजाते हैं लेकिन जब वीडिओज और बयानात के साथ डाक्टरी होने लगे तो नतीजा कन्हैया की शक्ल में निकल आता है और एक सीधा सादा विद्यार्थी टेररिस्ट और देश द्रोह बन जाता है इतना ही नहीं देशभक्ति के ठेकेदार उसको कोर्ट परिसर में घेर कर मारना चाहते हैं, 6 माह की जमानत पर आये कन्हैया जेएनयू परिसर में जब प्रवेश करते हैं तो उनके समर्थकों का समुन्द्र उमड़ जाता है और इस भवव्ये स्वागत से आत्म विभोर (गदगद) कन्हैया वो तमाम सत्यता सामने लाने का प्रयत्न करते हैं जिसकी हिम्मत बड़ी बड़ी हस्तियां आजतक नहीं कर पाईं थीं उनके खुलासों से बिलबिलाये संघियों ने भी उसकी स्पीच के खिलाफ पोस्टर्स निकाल डाले जिसमें उसकी जबान काटने वाले को 5 और सर काटने वाले को ११ लाख के इनाम की घोषणा करदी गयी।

बीजेपी सांसद योगी आदित्य नाथ उ.प्र. प्रभारी बनने की दौड़ और हविस में जेएनयू केम्पड़स में जिन्नाह का नाम लेने वालों को दफन करदेने की बात से नहीं चूके जबकि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्नाह की तारीफ तक कर चुके हैं उनको योगी कहाँ रखेंगे यह उन्होंने नहीं बताया।जब देश को बाहरी आतंक या हमलों का खतरा है ऐसे में देश की सत्ता धारी पार्टी के मंत्री देश में धार्मिक और जातिवाद की बड़ी लकीर खीचकर शायद देश के दुश्मनो के प्लान को आगे बढ़ाने का काम कररहे हैं। ऐसे में देश के मानव संसाधन मंत्री कठेरिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी को क्या कन्हैया पर हमला करने वाले चौलेंज करेंगे जबकि मंत्री के खिलाफ पेटिशन करने वालों में पहले ही चार जजों और पुलिस के आला रिटायर्ड अफसर शामिल हैं। याद रहे 04 मार्च को आगरा में मानव संसाधन मंत्री राम शंकर कठेरिया ने मुस्लिम मुखालिफ तकरीर में काफी अपशब्द कहे थे जिसपर देश के सेक्युलर रनकहमे और आला पुलिस अफसरों ने संज्ञान लेते हुए आरोपी मंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाली है।

यह सही वक्त है कि साम्राज्येवादी ब्रिटिश शासन के दौरान रॉलेट एक्ट का आना देश के क्रन्तिकारी सोच का दायरा बढ़ा रही थी यानी अपील, वकील और दलील पर पाबंदी लगाया जाना सबसे सनसनीखेज बन गया था। पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के सफल होने का यह बड़ा कारण बना था। आजादी के बाद तो हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को धर्म मानकर उसे सबसे ऊपर बनाए रखा। आज उसी एक्ट को दोहराया जारहा है जो क्रांति की नई शमा को रोशन कररहा है और वो है सामंतवाद, मनुवाद, पूंजीवाद, भुखमरी, साम्प्रदायिकता और जातिवाद से आजादी की क्रांति .इतिहास हमें याद दिलाता है की नैतिकता मुकम्मल तौर से समाज से नष्ट नहीं होती जब भी समाज में इंसानियत और ईमान ओ अमन पर आंच आती है तभी कुछ मतवाले नैतिकता की शमा को रोशन करते हैं और दुनिआ को घोर अँधेरे की रात से पहले प्रकाशमय करदेते हैं। ऐसे में कन्हैया को आज नैतिक एम्बेसडर मन जा रहा है और दुनिया उसके मुरीदों की तादाद बढ़ने के साथ इस बात की भी मुराद मांगी जा रही है की इस लाल की जान की हिफाजत हो, वरना कुछ राम के हत्यारे रावण की पूजा पर उतर आये हैं उनको सद्बुद्धि देना प्रभु।

Editor's Desk

संसद में दिखा सोहार्द का माहोल, विपक्ष ने सुषमा की तारीफ़ की

नई दिल्लीः जब देश में केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ असहिष्णुता और साम्प्रदायिकता भड़काने तथा वोट धुर्वीकरण की चर्चा है, ऐसे में लोकसभा में विपक्ष के नेताओं द्वारा सत्ता पक्ष की नेता सुषमा स्वराज की प्रशंसा किये जाना एक नेक फाल के साथ अच्छे कामों की सराहना का माहोल बनने की तरफ भी इशारा है पंजाब आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने प्रश्नकाल के दौरान कहा, मैं सुषमा स्वराज जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। वह विदेश में देशवासियों के लिए असाधारण रूप से अच्छा काम कर रही हैं। बीजू जनता दल (बीजद) नेता बीजे पांडा ने सुषमा स्वराज की प्रशंसा करते हुए कहा, एक मंत्री के रूप में उनका काम बेहतरीन रहा है।

प्रशंसा की इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सदस्य राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी पीछे न रहे और उन्होंने अंग्रेजी में पूछे गए सवाल का जवाब हिंदी में देने के लिए सुषमा स्वराज की तारीफ की।

जब खुलकर सुषमा के कामों की तारीफ हुई तो मेडम भी भाव विभोर हो उठीं और उन सभी विपक्षी नेताओं का खड़े होकर शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके कामों की प्रशंसा करते हुए कहा की हमको कोई प्रशन नहीं पूछना बस मेडम को शुक्रिया कहना है, इन विपक्षी नेताओं में आम आदमी पार्टी के ही धर्मवीर गांधी, बीजू जनता दाल के बी जे पांडा भी शामिल हैं। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अपने कार्यकाल में पहली बार ऐसा सोहाद्र देखकर आश्चर्य जताया और एक सांसद से कहा की कोई सवाल नहीं सिर्फ धन्यवाद!, वाह क्या बात है।

TOP BUREAU

RSS wing ABVP burns Manusmriti copies in JNU

On the International Women's Day, JNU students including former and current members of the ABVP, burnt copies of the Manusmriti to protest against "derogatory verses" towards women in the Hindu religious text.The students chose to send out the message that anything derogatory against women will not be tolerated. Vice-president of the ABVP unit in JNU, Jatin Goraiya said "Today is women's day and in order to oppose the derogatory remarks made against women in Manusmriti, we have burnt certain portions of the text" . The students burnt the pages of the text that contained 40 "derogatory" references against women.It is said in the manusmirti that Women, true to their class character, are capable of leading astray men in this world, not only a fool but even a learned and wise man. Both become slaves of desire". Pradeep Narwal, who recently left the ABVP citing "ideological differences," was one of the main organisers of the event. He read out the 40 points before burning the pages of the text."I have problems with these 40 points that are derogatory towards women and Dalits. If anyone thinks I am not right, they can tell me," he said.The students raised slogans such as Manuwad ho barbad, Brahmanwad ho barbad and Jatiwad ho barbad.

-Agency

Editor/Owner/Printer/Publisher: Ali Aadil Khan, K-2-A-001, Abul Fazal Enclave-I, Jamia Nagar, Okhla, ND - 25. **Printed at :** Shobi Offset Press, 2818, Gali Gadhiaiya, Kuchachalan, Daryaganj, ND. - 2

समाचार पत्रों के आईने से

देश की एकता व अखंडता के लिए मुसलमान, दलित और इंसाफपसन्द देशवासी एकजुट हो जाएंः मौलाना अरशद मदनी

नई दिल्लीः जमीअत उलमा–ए–हिंद ने बुधवार को नई दिल्ली के वल्लभ भाई पटेल हाउस के स्पीकर्स हॉल में एक भव्य पत्रकार सम्मलेन का आयोजन किया इस सम्मलेन को जमीअत उलमा–ए–हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सम्बोधित करते हुए तथा पत्रकारों के सवालों के जवाब में काफी कुछ कहा जिसके मुखय अंश ये हैं।

देश की वर्तमान स्थिति विभाजन के समय से भी अधिक खराब हैं। सरकार या सत्ताधारी पार्टी के विरोध को देशद्रोह करार दिया जा रहा है, पूरे देश में कानून की जगह ''आस्था'' की स्थापना और धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने की कोशिशें जारी हैं। मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों और कमजोर वर्गों पर अत्याचार, उत्पीड़न और हिंसा जारी है। कहीं आतंकवाद की आड़ में निर्दोष मुस्लिम युवकों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है तो कहीं 'मनुवादियों' का मुकाबला करने वाले दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों को न केवल देश विरोधी करार दिया जा रहा है बल्कि उन्हें आत्महत्या तक करने पर मजबूर किया जा रहा है। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की खाई बढ़ती जा रही है और दोनों एक दूसरे से भयभीत नजर आ रहे हैं। मुसलमानों को वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश की जा रही है और मुसलमानों और ईसाइयों की घर वापसी की बात हो रही है। अफसोस की बात तो यह है कि ''सर्व धर्म सुखाए'' की बात करने वाले भी अब हिंदू चरमपंथी संगठन आरएसएस से साठगांठ कर भाईचारा के पेड़ की जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं। सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा रही है और इस कोशिश में है कि कैसे मुसलमानों, अन्य अल्पसंख्यकों और दलितों को अलग कर दिया जाए।

हम न तो किसी विशेष पार्टी के समर्थक हैं और न ही विरोधी। हम केवल उस मानसिकता के विरोधी हैं जो देश की एकता और अखंडता को नष्ट करने में लगी है और हम देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं। देश में एक और विभाजन की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान सरकार अच्छे दिन लाने के वादे को भुलाकर संघी अजेंडे को आगे बढ़ाने में व्यस्त है और सिमटकर नागपुर व झंडेवालान पर आ गई है। सत्ताधारी दल के कुछ लोग देश की पहचान को मिटाने में मसरूफ हैं और हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को और गहरा किया जा रहा है। मुसलमान कभी भी गौ–हत्या का समर्थक नहीं रहा बल्कि हम तो कहते आए हैं कि आप गाय को 'राष्ट्रीय पशु' घोषित कर दीजिए, आखिर इस से आपको परहेज क्यों है?वास्तविकता तो यह है कि देश में मोदी सरकार के आने के बाद 'बीफ' के व्यापार को बढ़ावा मिला है।

देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमानों को आतंकवाद के फर्जी मामलों में फंसाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। आतंकवाद की आड़ लेकर इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने का प्रयास जारी है और उलमा के साथ साथ उच्च शिक्षित निर्दोष मुस्लिम युवकों को फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है, ताकि उन्हें हतोत्साहित करके मुसलमानों में निराशा का वातावरण बनाया जा सके। वर्तमान सरकार सभी प्रमुख शैक्षिक संस्थानों का भगवाकरण करने में व्यस्त है और हाल ही में जे.एन.यू. में जो कुछ हुआ यह उसका उदाहरण है। वर्तमान सरकार देशभक्ति की नई परिभाषा करके उसे अपने अनुसार बनाने की

कोशिश कर रही है। स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार के विरोधियों को राष्ट्र–विरोधी करार दिया जा रहा है।

ऐसा नहीं है कि हालात केवल मुसलमानों के लिए ही खराब हैं बल्कि दलितों की स्थिति भी जानवरों से बदतर है। सरकार में शामिल मंत्री ही दलितों की तुलना जानवरों से कर रहे हैं। कल तक जो लोग खुद को दलितों का मसीहा कहते थे और उनके वोटों से विजयी हुए थे आज आर.एस.एस. के वफादार बनकर न केवल सत्ता का आनंद ले रहे हैं बल्कि दलितों को बेसहारा छोड़ दिया गया है। इसलिये जमीअत ने दलित नेताओं से संपर्क स्थापित करके उनसे साथ आने की अपील की है और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने की घोषणा की है। हरियाणा में''जंगल राज'' है और वहां 40 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति को नष्ट कर दिया गया यह केवल भाजपा सरकार की नाकामी है ? अगर यही सब मुसलमानों या दलितों ने किया होता तो भी क्या हरियाणा सरकार और पुलिस का यही रवैया होता अफसोस कि खुद को ''प्रधान सेवक'' कहने वाले मोदी जी मूकदर्शक हैं

जमीअत उलमा–ए–हिंद देश की इन परिस्थितियों पर बहुत चिंतित है और उसकी एकता, अखंडता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, संविधान, सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण के लिए अपनी हर संभव सेवाएं प्रदान करने को तैयार है।

TOP BUREAU

मराठवाड़ा में किसान ने की आत्महत्या, परिजनों का आरोप – सरकार हमें मार रही है

मुंबईः यह आत्महत्या नहीं हत्या है। मराठवाड़ा के सूखाग्रस्त इलाके में एक किसान की मौत पर उसके परिजनों का यह आरोप है। बारिश की बूंदें बरसी नहीं है, जलाशयों में 6 फीसदी से भी कम पानी बचा है, ऐसे में मॉनसून का इंतजार किसानों पर बहुत भारी पड़ रहा है।

महाराष्ट्र में लातूर के उजनी गांव में 45 साल के संजय जाधव ने खुदकुशी कर ली। उनके साले अण्णासाहिब पाटिल का सीधे–सीधे आरोप है हम पूरे देश का पेट भरते हैं और हम खुद भूखे हैं। पूरा देश खाना खा रहा है और यहां हम मर रहे हैं, लेकिन यह मौत नहीं है, सरकार हमें मार रही है। हम मर नहीं रहे हैं, सरकार हमारी हत्या कर रही है।

मंत्रियों के दौरे से पहले हुई घटना

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस सहित 28 कैबिनेट मंत्रियों के मराठवाड़ा दौरे से ठीक पहले संजय जाधव ने जहर पीकर जान दे दी। लगातार पड़ रहे सूखे और 3 लाख के कर्ज ने संजय को लगभग खत्म कर दिया, ऊपर से पिता के कैंसर के इलाज के लिए एक लाख रुपये का कर्ज। पिता को कैंसर ने मार डाला, बेटे को कर्ज ने।

मराठवाड़ा के जलाशयों में सिर्फ 6 फीसदी पानी

ज्यादातर इलाकों में खुदकुशी की बड़ी वजह है सूखा। मराठवाड़ा के जलाशयों से 6 फीसदी से भी कम पानी बचा है। सन 2015 में इन्हीं जलाशयों में 18 फीसदी से ज्यादा पानी था। मराठवाड़ा के मांजरा डैम से बीड़, उस्मानाबाद और लातूर को पानी सप्लाई होता था लेकिन अब यह लगभग खाली हैं। यहां रहने वाले किसान प्रकाश तेले का कहना है यहां पानी भरा रहता था, लेकिन पिछले दो सालों से पानी नहीं भरा। अब कुछ नहीं बचा है। किसानों के साथ खतरे में उनके मवेशी भी हैं। मदद के लिए सरकार अब जमीन पर उतरी है, लेकिन शायद बहुत देर से।

NOTICE:
Times of Pedia does not guarantee, directly or indirectly, the quality or efficacy of any product or services described in the advertisements or other material which is commercial in nature in this Newspaper. Furthermore, Times of Pedia assumes no responsibility for the consequences attributable to in accuracies or errors in the printing of any published material from the news agencies or articles contributed by readers. It is not necessary to agree with the views published in this Newspaper. All disputes to be settled in Delhi Courts only.

ट्रेनों में महिला यात्री अब फोन कर बदलवा सकेंगी अपनी सीट

मदुरैः ट्रेनों में अकेले सफर करने और सीट बदलने की इच्छा रखने वाली महिला यात्री अब एक वरिष्ठ महिला रेल अधिकारी की मदद से ऐसी सेवाओं का लाभ ले सकेंगी। एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि कई महिलाओं से ऐसा अनुरोध मिलने के बाद कि वह पुरुष यात्रियों के बीच आवंटित की जाने वाली सीट पर असुरक्षित या असहज महसूस करती हैं। सहायक वाणिज्य प्रबंधक रैंक के अधिकारी उन्हें सहायता प्रदान करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। वे 9003160980 नंबर पर उनसे संपर्क कर सकती हैं।

महिलाओं को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि शिकायत असली है और परिस्थिति वास्तव में खराब है। उन्हें अपना नाम और मोबाइल नंबर बताना होगा। विज्ञप्ति में बताया गया है कि इन सुविधाओं के अलावा महिलाएं बचाव एवं सुरक्षा के लिए 24 घंटे काम करने वाली विशेष सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 पर संपर्क कर सकेंगी।

इशरत मुठभेड़ में मोदी-शाह से होगी पूछताछ

अहमदाबादः मुंबई की कॉलेज छात्रा इशरत जहां और उसके तीन साथियों के फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र और गृह राज्यमंत्री अमित शाह संदेह के घेरे में हैं। हम अन्याय के खिलाफ हैं और अन्याय की आवाज हम उठाते रहेंगे। जुर्म और जालिम ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा।

सीबीआइ मुठभेड़ के आरोप में गिरफ्तार आइपीएस जीएल सिंघल के खिलाफ 90 दिन बाद भी आरोपपत्र दाखिल करने में नाकाम रही थी। अंदेशा है कि सीबीआइ सिंघल को सरकारी गवाह बनाकर मोदी और शाह तक पहुंचना चाहती है। जांच एजेंसी दोनों नेताओं को समन जारी कर पूछताछ की तैयारी कर रही है।

कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल ख्एसआइटी, ने इशरत जहां और उसके तीन साथी जावेद शेख, अमजद अली व जिशान जौहर को मुठभेड़ में मार गिराने की जांच की थी। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि गुजरात पुलिस ने इशरत व उसके साथियों को फर्जी मुठभेड़ में मारा था। इस मामले में भी पूर्व आइपीएस डीजी वणजारा की अहम भूमिका बताई गई है, जो करीब पांच साल से सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में मुंबई जेल में बंद हैं। फरवरी 2013 को सीबीआइ ने इशरत मामले में आइपीएस जीएल सिंघल की धरपकड़ की थी। इससे पहले पुलिस उपाधीक्षक व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तरुण बारोट, जेजी परमार, भरत पटेल को भी गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि सीबीआइ के संयुक्त निदेशक वीवी लक्ष्मी मार्च 2013 में गुजरात आए थे। साबरमती जेल में उन्होंने आइपीएस सिंघल से भी लंबी चर्चा की थी, जिसके चलते सिंघल व सीबीआइ के बीच कुछ आपसी समझौते की भी आशंका जताई जा रही है।

जीएल सिंघल ने शुक्रवार को सीबीआइ की विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर सोमवार को फैसला होना है। सिंघल ने दलील दी है कि 90 दिन बाद भी सीबीआइ उनके खिलाफ आरोपपत्र पेश नहीं कर पाई है।

चर्चा है कि सीबीआइ सिंघल को सरकारी गवाह बनाकर इशरत मुठभेड़ मामले से राजनीतिक तार जोड़ने का प्रयास कर रही है। सिंघल व उनके साथियों के जमानत पर बाहर आने के बाद फिर उनकी गिरफ्तारी की आंशका कम होगी।

—एजेंसी

Tahir ul Qadri protected by Blackwaters

Reports published in Urdu press in Pakistan have confirmed that Tahir ul Qadri is a CIA agent whose protection and security on his trip to India is with Blackwaters, a notorious Anti-Muslim security agency formed by ex-US army personnel and CIA agents. The havoc of major bomb blasts in Iraq, Afghanistan and Pakistan killing hundreds of thousands of people in last two decades have all been carried out by this ruthless terror security agency as has been reported in global media regularly.

Tahir ul Qadri resides in Canada but is a citizen of Pakistan with billions of dollars working to divide Sunni Muslims with Zionist funding and support.

Why the most expensive Anti-Muslim security agency was protecting Tahir-ul-Qadri when asked to explain the Minhaaj ul Quraan office refused. On the other hand advertisements have been placed by Hyderabad Minhaaj ul quran in MIM official organ Urdu Daily Etemaad, thanking Assaduddin Owaisi and others for supporting Tahir ul Qadri in his India visit.

CROSSINGS Republik™

READY 2 MOVE IN FLATS

in

CROSSINGS REPUBLIC-NH24

India's First Global city

- 9 KM from Noida City Centre,
- 15 km from Kalindikunj
- 12 km Anand Vihar
- Just Adjacent to Noida Extension
- Approx 200 families already shifted
- Club/Swimming pool
- Power backup/market complex
- Huge jogging track
- Magnificent golf course in order
- 80% open area
- A Unique complex in whole of NCR

SIZE : 2 bed room 1270 sq ft. • 3 bed room 1725 ft.
nicely built-up flats vitrified tiles, wooden flooring in master bedroom, complete tiling and sanitary fittings in bathrooms, kitchen, large dinning/drawings/4 balconies
PRICE: 2 bed room 28-lacs onwards • 3 bed room 38 lacs onwards
all inclusive (Covered car parking, club membership, power back up 1 KV, EDC/FFC/IFMC etc.)

Contact:

CITY ESTATE

A real estate service provider and Marketing Channel Partner of many reputed builders in NCR

Branch Offices: • 301, JOP Plaza, Sector 18, Noida • Shop No 22, Gallaria Complex, Crossings Republic.
Email: city_realestate@yahoo.co.in

मानव भविष्य बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने आसपास पेड़ लगाएं और गंदगी न होने दें।

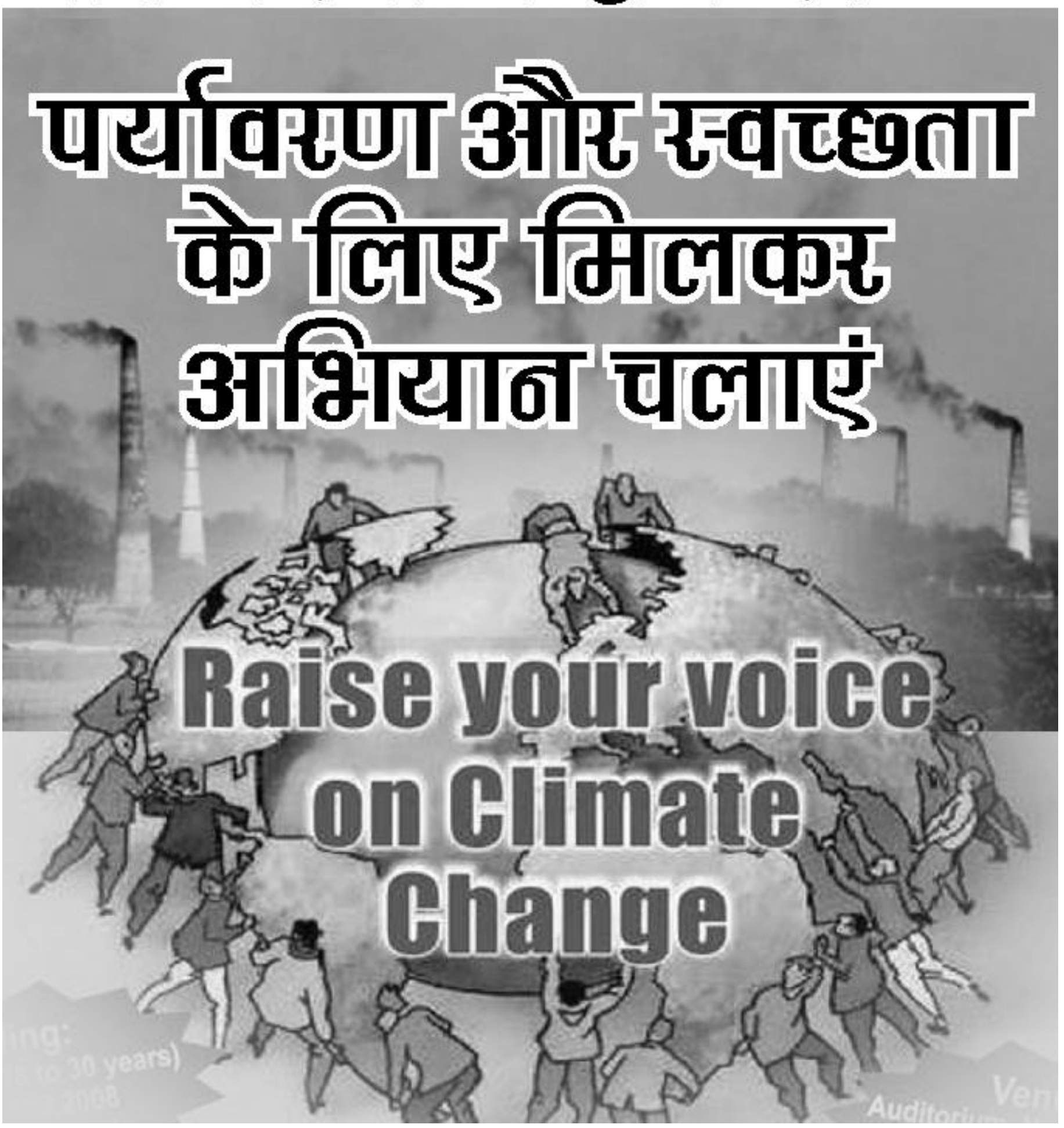

राम मंदिर के बाद राष्ट्र मंदिर की राजनीति

उत्तर प्रदेश में चले राम मंदिर आंदोलन ने उत्तर प्रदेश को कम से कम 20 साल पीछे धकेल दिया। न राम मंदिर बन पाया और न उत्तर प्रदेश। बीजेपी दोनों को छोड़कर आगे बढ़ गई।

उस राम मंदिर आंदोलन के अलग–अलग सिरों को याद करें तो पाएंगे तो देश के सामने खड़े कई संकटों के बीज वहीं थे। इसी आंदोलन की वजह से 1992 की बाबरी मस्जिद टूटी, मुंबई में दंगे हुए और 1993 में इस शहर ने आतंकी धमाके देखे। इसी आंदोलन के क्रम में 2002 में अयोध्या से चली कारसेवकों की बोगी गोधरा में जली, गुजरात में दंगे हुए और उसके बाद माहौल में एक जहर घुल गया। इनके सामाजिक–आर्थिक नुकसानों की वास्तविक ऑडिटिंग होनी बाकी है। इसकी वजह से कितने छोटे–बड़े कारोबार प्रभावित हुए, कितने लोगों ने भारत में निवेश का इरादा छोड़ा– इन सबका हिसाब शायद कभी नहीं लगाया जा सकेगा। लेकिन अब वह सब पीछे छोड़कर बीजेपी आगे बढ़ चुकी है। उसे लग रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा अब और नहीं चलेगा। अब वह एक नया मंदिर बनाने की कोशिश में है– यह है राष्ट्र–मंदिर। कौन नहीं चाहेगा कि ऐसा राष्ट्र मंदिर बने और उसमें भारत माता की प्रतिमा स्थापित हो।

अपनी बहुत सारी गड़बड़ियों के बावजूद राष्ट्र अब तक हमारे भीतर एक स्पंदन पैदा करता है– एक गरिमा का भाव। लेकिन वह भारत माता कौन सी है जिसे हम पूजें?यह सवाल आजादी की लड़ाई के दौर में नेहरू ने भारत माता की जय का नारा लगाने वालों से पूछा था। बाद में सुमित्रानंदन पंत ने कविता लिखी, 'भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा–जमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी।श इसी कविता का 'मैला आंचल' रेणु के यहां उपन्यास में बदल गया। दरअसल यह सब देश को समझने–पहचानने की कोशिश थी– वह कविता, वह गद्य लिखने की कोशिश जिसका नाम भारत है। दिनकर ने इसी देश के लिए लिखा था कि 'भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है।

लेकिन यह कविता किसी मुग्ध भाव से नहीं लिखी जा रही थी, इस गद्य के पीछे कोई उन्माद नहीं था। इसी दौर में अपने नाटक 'चंद्रगुप्त' में प्रसाद मगध के विलासी शासकों से कुपित चाणक्य के मुंह से कहला रहे थे, 'क्या राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने इसीलिए किया था?मगध–मगध, सावधान! इतना अत्याचार सहना असंभव है। तुझे उलट दूंगा। नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही कर दूंगा।श कहने की जरूरत नहीं कि मगध के इस रूपक का इस्तेमाल करते हुए प्रसाद को राष्ट्रवाद के उन्मादी खतरों का एहसास था। इसी दौर में संभव था कि एक शायर सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा लिख सकता था और दूसरा पूछ सकता था कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां हैं।

भारत की कविता कहीं पीछे छूट गई है, भारत को समझ सकने वाला गद्य कहीं खो गया है। यह समझ भी बेमानी होती चली जा रही है कि राष्ट्रों की कोई जड़ मूर्ति नहीं हो सकती, वे हमेशा हिलते–डुलते, स्पंदित होते, और वक्त के हिसाब से बदलते संगठन ही होते हैं। इन सबकी जगह बस भारत माता की जय के नारे ने ले ली है। यह सबसे आसान है।

भारत माता की जय का नारा लगाया और देशभक्त हो गए। इतना नारा भर लगा लेने से आपको कानून तोड़ने का, दंगे करने का, भ्रष्टाचार करने का, महिलाओं से बलात्कार करने का लाइसेंस मिल जाता है।

इन दिनों ऐसी ही देशभक्ति उफान पर है– एक बहुत आसान किस्म की देशभक्ति, जिसके लिए न कोई त्याग करना पड़ता है, न किसी मर्यादा का पालन करना पड़ता है। बस उन लोगों को डराना–धमकाना और कभी–कभार पीटना होता है जो देश की इस अवधारणा को स्वीकार नहीं करते और मानते हैं कि देश की सेहत के लिए देश पर भी बहस जरूरी है।

भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही देशभक्ति के सहारे अब राष्ट्र मंदिर की राजनीति करने चली है। हैदराबाद के रोहित वेमुला, और जेएनयू के उमर खालिद और कन्हैया मिलकर उसके लिए प्रतिरोध की जो चट्टान बना रहे हैं, उसका सामना वह उन्माद की नदी बहाकर ही कर सकती है। इसलिए वह जेएनयू में कुछ शरारती तत्वों द्वारा लगाए गए चंद नारों को देश के लिए खतरनाक बता रही है। वह पूरे देश में ऐसा माहौल बनाने में लगी है जैसे जेएनयू किन्हीं बाहरी खुफिया और दहशतगर्द एजेंसियों और संगठनों का ठिकाना हो जहां सिर्फ अय्याशी और देशद्रोह के नारे चलते हैं और जो लोग इसके समर्थन में खड़े हैं, वे भी गद्दार हैं। जबकि जेएनयू क्या है, वह अपने छात्रों को कैसी शिक्षा देता है और इस देश को कितने सारे जेएनयू चाहिए– यह बताने के लिए सिर्फ कन्हैया के बीते दिनों दिए गए भाषण ही पर्याप्त हैं।

मामला जेएनयू के विरोध का नहीं है। बीजेपी और संघ परिवार को सिर्फ जेएनयू नहीं, कोई ऐसा संस्थान नहीं चाहिए जहां विवेक और वैज्ञानिक तर्क की बात होती है– जहां इतिहास, समाज–विज्ञान या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नए शोध होते हों जो आधी–अधूरी धारणाओं को चुनौती देते और उन्हें ध्वस्त करते हों। उन्हें बस ऐसे करिअर बनाऊ इंस्टीट्यूट चाहिए जहां बच्चे दो साल पढ़ाई करें और फिर किसी नौकरी में लग जाएं– वे रुपये कमाने की जगह डॉलर को तरजीह दें और दिल्ली की जगह न्यूयॉर्क में भी रहना चाहें तो कोई यह नहीं पूछने वाला है कि उन पर हुई पढ़ाई की लागत किसके काम आ रही है। जो इससे इतर, छात्रों को कुछ सोचने–समझने का, लोकतंत्र, न्याय और बराबरी पर बहस करने का सबक सिखाते हैं, वे मंजूर नहीं किए जा सकते। तो यह सिर्फ जेएनयू में नहीं हो रहा, यह संस्थानों की सामूहिक हत्या का काम है जो लगातार चल रहा है।

क्योंकि बीजेपी अब राजनीति का नया एजेंडा बनाने की कोशिश में है। भव्य राम मंदिर के बाद वह राष्ट्र मंदिर का सपना बेच रही है। लेकिन जैसे राम मंदिर नहीं बना, वैसे ही राष्ट्र मंदिर भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वह इस देश की मूल आत्मा के खलिफा है। मगर इस कोशिश में जैसे यूपी पीछे छूटा, इस बार भारत पीछे छूट जाएगा। क्योंकि यह थोपी हुई देशभक्ति– 270 फुट के तिरंगों के सहारे रोपा जाने वाला राष्ट्रवाद सिर्फ भय, संशय और टूटन पैदा करेंगे, गरिमा और गौरव का वह भाव नहीं, जुड़ाव और आत्मीयता का वह देशज ठाट नहीं, जिसके बीच कोई कन्हैया जेएनयू के छात्रों, खेतों के किसानों और सीमा के जवानों को एक साथ जोड़ सकता है। एक विराट, भरे–पूरे, विविधतापूर्ण, बहुलतावादी, गंगा–जमनी भारत को खत्म करके ही ऐसा राष्ट्र मंदिर बनाया जा सकता है– जो सच्चे भारतीयों को किसी हाल में मंजूर नहीं होगा।

(प्रियदर्शन एनडीटीवी इंडिया में सीनियर एडिटर हैं)

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति टाइम्स ऑफ पीडिया उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार टाइम्स ऑफ पीडिया के नहीं हैं, तथा टाइम्स ऑफ पीडिया उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

उत्तर प्रदेश का मिशन 2017 तैयारी में कहां है बीजेपी...?

नए वर्ष का एक और महीना बीत जाने के साथ उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव और पास आ गए हैं। प्रदेश में जहां तीन प्रमुख राजनीतिक दल प्रचार–प्रसार, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी और आक्रामकता के दम पर अपना घर मजबूत कर रहे हैं, वहीं चौथा प्रमुख दल एक के बाद एक हार का सामना करते हुए दिशा की तलाश करता दिख रहा है। सच तो यह है कि 2017 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में चार प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए हार–जीत से कहीं ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो गया है।

पहले कांग्रेस को लें। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता आजकल अति–उत्साहित हैं। देश में और लोकसभा में तमाम मुद्दों पर उनके नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे–सीधे चुनौती दे रहे हैं, एक नए किस्म की आक्रामकता दिखाकर राहुल यह स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर देश के किसी और राजनीतिक दल के नेता में मोदी को सीधे टक्कर देने की क्षमता है, तो वह सिर्फ उनमें है। जाहिर है कि लम्बे समय से निष्क्रिय पड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रादेशिक नेताओं के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं है।

गत 2 मार्च को दिल्ली में हुई एक बहुचर्चित बैठक में उत्तर प्रदेश के एक दर्जन से ज्यादा कांग्रेस नेताओं को बुलाया गया था और उनसे पूछा गया कि प्रदेश में कांग्रेस को फिर प्रासंगिक बनाने के लिए उनके क्या विचार हैं। खास बात यह थी कि उनके विचार सुनने के लिए शीर्ष नेताओं के अलावा हाल ही में सुर्खियों में छाए प्रशांत किशोर भी शामिल थे। किशोर को कांग्रेस पार्टी ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में पार्टी की चुनावी नैया पार लगाने के लिए साथ में लिया है। चूंकि किशोर इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और मोदी के लिए जीत की प्लानिंग के लिए जिम्मेदार माने जाते थे, इसलिए पिछले वर्ष हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल (यूनाइटेड) ने उन्हें नीतीश कुमार के लिए वैसी ही प्लानिंग करने के लिए अपने साथ जोड़ा था। इस प्रयोग के भी सफल हो जाने के बाद अब किशोर देश में नंबर वन राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं।

उत्तर प्रदेश के तमाम नेता अब यह मान के चल रहे हैं कि किशोर कुछ ऐसी योजना बनाएंगे कि न केवल राहुल राष्ट्रीय स्तर पर अपना सिक्का जमाएंगे, बल्कि प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को जीत का रास्ता दिखाएंगे। प्रियंका गांधी के लिए कोई बड़ी भूमिका की खबरें आने के बाद तो प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और अन्य तमाम नेता भी निश्चिन्त हो चले हैं कि अगले चुनाव में कांग्रेस के अच्छे दिन आने ही वाले हैं।

सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के लिए 2017 की हार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के राजनीतिक करियर पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा सकती है। फिलहाल तो प्रदेश सरकार विज्ञापन और घोषणाओं के दम पर अपनी पहचान मजबूत करने में लगी हुई है। सत्ता में होने का जो भी लाभ उठाया जा सकता है, वह उठाया जा रहा है।

मुख्य विपक्षी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के पास यह अंतिम मौका होगा कि वह प्रदेश और देश की राजनीति में खुद को फिर स्थापित कर सकें। पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट न जीत पाने का मलाल मायावती को किस कदर है, इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अब अपने परंपरागत प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ भी टिप्पणी करना लगभग बंद कर दिया है और उनके सारे बयान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही होते हैं। अपने दलित समर्थकों के छिटककर भारतीय जनता पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए उन्हें मोदी और बीजेपी को दलित–विरोधी सिद्ध करना अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए जितना जरूरी आज है, उतना शायद कभी न था।

लेकिन इन सबके बावजूद बीजेपी में वर्तमान दिशाहीनता का दौर समाप्त होता ही नहीं दिख रहा है। वर्ष 2012 से अब तक हुए सारे उपचुनाव हारने के बाद पार्टी को केवल एक जीत मुजफ्फरनगर में मिली, और अभी समाप्त हुए विधानपरिषद के चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पार्टी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और शीर्ष नेताओं के बड़े–बड़े दावों के बावजूद एक भी जीत न हासिल करना पार्टी में गहरी बीमारी की ओर संकेत करता है। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष स्वयं नहीं जानते कि उन्हें कितने दिन और कार्यवाहक के रूप में काम करना है, अन्य पदाधिकारी इस असमंजस में हैं कि नए अध्यक्ष आने के बाद उनका क्या होगा, वरिष्ठ नेता इस बात से ही परेशान हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उन्हें पहचानते भी हैं कि नहीं।

पार्टी के कुछ पदाधिकारी नाम न बताने के आग्रह के साथ कहते हैं कि पिछले साल प्रदेश से एक सदस्य राज्यसभा जा सकता था, लेकिन उस सीट पर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को संसद भेजा गया, और उसके बाद से ही प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में अपने उपेक्षित होने की भावना घर कर गई है। प्रदेश के नेता यह मानकर चलने लगे हैं कि लोकसभा में 73 सदस्य उत्तर प्रदेश से होने के बावजूद यदि प्रदेश में पार्टी के लिए कुछ निर्णय लिया जाना है तो वह केंद्रीय स्तर पर ही लिया जाएगा। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम उत्तर प्रदेश में किसी प्रमुख भूमिका के लिए उछलने के बाद भी इस भावना को ही बढ़ावा मिला था। ऐसे में प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिशन 2017 के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं।

रतन मणिलाल वरिष्ठ पत्रकार हैं...

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति टाइम्स ऑफ पीडिया उत्तरदायी नहीं है। आलेख ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया गया हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार टाइम्स ऑफ पीडिया के नहीं हैं, तथा टाइम्स ऑफ पीडिया उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

इस क्रांतिकारी की सजग सरलता का मुरीद होने लगा देश

वह देशभक्ति का झरना–सा बहाता चला गया। कन्हैया कुमार का 50 मिनट का तार्किक भाषण सुनते हुए उन लोगों को भी पता चल रहा होगा, जिन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि अपने एक छात्र की नैतिक सुरक्षा में जेएनयू के प्रोफेसर सड़क पर क्यों निकल आए थे। अंदाजा है कि गुरुवार की रात जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद कन्हैया को सुनकर विश्व के तमाम विश्वविद्यालयों के परिसरों में छात्र अभिभूत हो गए होंगे। कन्हैया के भाषण की दूसरी भाषाओं में डबिंग शुरू हो गई होगी। याद नहीं पड़ता कि तार्किकता का ऐसा प्रभुत्व कायम होते कब दिखा था।

देश में कहने–बोलने में बढ़ते भय के बीच जेएनयू मामले के इतना बढ़ जाने के कई कारण हो सकते हैं। आगे–पीछे सारी बातें पता चलेंगी, लेकिन इस मामले ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, सांप्रदायिकता और ऐसे दूसरे मुद्दों पर सोच–विचार के लिए एक बड़ा मौका पैदा कर दिया। जेएनयू में कन्हैया के भावपूर्ण नेतृत्व में घंटे भर के इस अपूर्व आयोजन में वाद्ययंत्रों की जरूरत नहीं पड़ी। आयोजन के फौरन बाद सोशल मीडिया पर कन्हैया का क्रांतिगीत ट्रेंड होने लगा। अब जल्द ही पलटकर इस बात भर भी ध्यान जाएगा कि जेएनयू का मामले का आगा–पीछा है क्या...?वक्त जितना भी लगे।

फिलहाल हमारे पास ऐसा इंतजाम नहीं है कि जेएनयू प्रकरण पर निर्विवाद राय दे सकें, क्योंकि माहौल ऐसा बना दिया गया है कि हर मशविरे को मामले के किसी पक्षकार की वकालत माना जाने लगा है। इसके साथ ही कन्हैया प्रकरण के जरिये कुछ दिनों के लिए तार्किकों के खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया गया था कि उनके बोलते ही वे अविश्वसनीय लगने लगें। फिर भी अकादमिक स्तर पर कुछ जटिल बातों पर चर्चाएं शुरू होना स्वाभाविक है।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। एक पहचान समानता के रूप में हुई थी, लेकिन आग्रही और जिद्दी वर्ग ने हमेशा ऐसा माहौल बनाए रखा कि हम कभी भी इस बात का आम राय से ऐलान कर नहीं पाए। जरूरत पड़ने पर कभी–कभी सैद्धांतिक रूप से इसे मान लेते हैं, लेकिन व्यवहार में समानता का प्रभुत्व दिखाई नहीं देता। श्हमश की भावना वाले समाज के रूप में भी लोकतंत्र को परिभाषित नहीं होने दिया जाता। कुछ लोग धर्म, कुछ लोग जाति और कुछ भौगोलिक क्षेत्र की अपनी–अपनी अस्मिता का फच्चर फंसा देते हैं। यानी श्हमश वाले भाव के सामने मैं वाले भाव को लाकर खड़ा कर देते हैं।

ऐसा नहीं है कि यह तय न हो सके कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन इसके लिए सोच–विचार और वाद–विवाद की जरूरत पड़ती है। यहीं पर वह स्थिति आ सकती है कि अस्मितावादी कहें कि अस्मिता के मामले में तो कोई बात सुनने का सवाल ही नहीं। बहुत संभव है, इसीलिए होता हो कि सही–गलत का फैसला करने के वाद–विवाद पर पाबंदी लगने या लगाने की सूरत बनती हो।

गांधी, नेहरू, इंदिरा, राजीव, अटल, मनमोहन और मोदी के अपने–अपने दौरों में लोकतंत्र के विकास–अविकास के मामले में क्या हुआ, इसका कोई निर्विवाद लेखा–जोखा बन नहीं पाया है। आजाद भारत के शुरुआती दशकों में जब अभिव्यक्ति की चरम–परम स्वतंत्रता का दौर था, तब भी आजादी के बारे में या समानता के बारे में और उसे हासिल करने के बारे में हानिरहित उपायों को ढूंढते ही रहे। इसी तलाश में वाद–विवाद और संवाद होते हैं। वाद–विवाद की पहली जरूरत अभिव्यक्ति की आजादी होती है।

यहां यही विषय है। जाहिर है, इस बारे में कुछ भी सोचने की प्रक्रिया में बाधा के रूप में बौद्धिक अधिनायकवाद या बौद्धिक आतंकवाद का विषय डाला ही जाएगा। डाला क्या जाएगा, लगभग डाल दिया गया है। बुद्धिजीवी वर्ग के सामने यह बिल्कुल नई चुनौती है। खासतौर पर तर्कशास्त्रियों पर यह जिम्मेदारी आन पड़ी है कि बहुत कम समय लगा साफ करें कि बौद्धिकता या बौद्धिक कर्म या विचार–विमर्श किसी भी रूप में आतंकवाद हो भी सकता है या नहीं।

पूरे देश में 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में नैतिकता की परिभाषा पढ़ाई जाती है। इसमें बताया जाता है कि सही और गलत का फर्क समझना ही नैतिकता का काम है। इस पाठ्यक्रम में बच्चों पर ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता। उन्हें नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र के सरल– सरल– से सिद्धांत बता दिए जाते हैं, ताकि वे आगे के जीवन में सही– गलत के फर्क को समझने लायक हो जाएं। तर्कशक्ति बढ़ाने के लिए इन बच्चों में निबंध लिखने की क्षमता बढ़ाने की कवायद की जाती है। निबंध लिखने के लिए उसे निर्बंध कर दिया जाता है। उसे बने–बनाए उपदेश नहीं दिए जाते कि इस विषय पर निबंध के लिए यही विचार लिखना है। हां, समाज विज्ञानों की पढ़ाई के बाद इम्तिहान में विद्वानों द्वारा सत्यापित विचार ही लिखने होते हैं, जो बहुत सोच–विचार के बाद, यानी वाद–विवाद के बाद ही बने होते हैं। यानी, हर स्तर पर सही–गलत के फैसले विचार–विमर्श से ही होते हैं।

दुनियाभर की सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के न्यायतंत्र में आज तक भी सुनवाई या बहस का चलन है। एक से एक खूंखार राज व्यवस्था में भी सजा देने से पहले आरोपी को तफसील से सुनने की रस्म जरूर निभाई जाती है, लेकिन अगर सही और गलत के बीच फैसले की प्रक्रिया में प्रतिवादी को सुनवाई से पहले ही मारने या सजा देने की तरफदारी की जाने लगे तो क्या भारी चिंता की बात नहीं है।

यह बात पहले से सनद है और काम आने लिए यह सही वक्त है कि ब्रिटिश शासन के दौरान रॉलेट एक्ट का आना, यानी अपील, वकील और दलील पर पाबंदी लगाया जाना सबसे सनसनीखेज पर्व था। पूरे आंदोलन के सफल होने का यह बड़ा कारण बना था। आजादी के बाद तो हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को धर्म मानकर उसे सबसे ऊपर बनाए रखा। उसे इतना महत्व दिया कि किसी आपातस्थिति में उस पर अस्थायी पाबंदी के लिए संविधान में प्रबंध तक किया, ताकि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में भेद की गुंजाइश बनी रहे।

यानी, ऐसा भी कतई नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छदंता की विकट परिस्थिति में आपातकाल लागू करने का संवैधानिक और नैतिक प्रबंध न कर रखा हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे अपने भूखंड में ही पाया जाता है। वह बताता है कि संकट का समय गुजरते ही हालात बहाली भी कितनी आसानी से हो सकती है। सनद रहे, आपातकाल हटाए जाने के लिए हिंसा या अनैतिक उपायों का अस्त्र चलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। आपातकाल संवैधानिक व्यवस्था से ही हटा था। आपातकाल लगाने वाली सत्ता ने जनता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल की थी।

जेल में बंद आपातकाल से पीड़ित वर्ग आपातकाल हटने के फैसले से भौंचक रह गया था। लोकतंत्र और तंदुरुस्त होकर और आगे बढ़ा था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही कमाल था कि आपातकाल के पीड़ित वर्ग को सत्ता मिल गई थी। वह अलग बात है कि अभिव्यक्ति की आजादी का ही कमाल था कि कार्यकाल खत्म होने से पहले ही जनता ने उन्हें नकार भी दिया था। अभिव्यक्ति की आजादी का उससे भी बड़ा कमाल देखिए कि उसी जनता ने आपातकाल लगाने वाली सत्ता को फिर सत्ता में ला दिया। यानी अब तक कुख्यात बताया जाने वाला आपातकाल तक हमारे लोकतांत्रिक न्यायतंत्र की मर्यादाओं से होकर गुजरा था। ऐसा तो तब भी नहीं हुआ था कि आपातकाल का ऐलान किए बगैर बोलने–कहने पर पाबंदी लगाने की कोशिश होने लगे। ऐसे मुद्दों पर सोच–विचार की बातें हम गली–कूचे में बैठे पत्रकार या मीडिया के ग्राहक बेखौफ होकर नहीं कर सकते।

अरे, जब निरे रुपये–पैसे का हिसाब करने वाला देश का बजट समझाने में ही परेशान दिखे, तो लोकतंत्र या अभिव्यक्ति की आजादी जैसी जटिल बातों को छोटे वाले विद्वान क्या समझा पाएंगे। अपनी–अपनी विचारधारा को जान–सा प्यारा मानने का आग्रह रखने वाले लोग दूरअंदेशी बातों को समझने के पचड़े में क्यों पड़ेंगे... ?बचते हैं वे विद्वान, जिनका उद्यम ही, यानी काम ही सोचना–समझना है। ऐसे में सारी जिम्मेदारी इन पढ़ने–पढ़ाने वाले अकादमिक लोगों पर आना स्वाभाविक है।

उनके अलावा अकादमिक रुझान के लेखकों–पत्रकारों से हमेशा ही उम्मीद लगी रहती है। लेकिन इन सबको हम मुश्किल में पड़ता देख रहे हैं। उनकी विश्वसनीयता पर हमला, भौतिक धक्का–मुक्की का डर, देशद्रोह के भावनात्मक आरोपों का बढ़ता प्रजनन फिर भी उतने बड़े संकट नहीं है। विद्वानों को फुसलाया जाना ज्यादा बड़ा संकट दिख रहा है। अगर वाकई ऐसा हो रहा होगा तो यह अंदेशा भी है कि यह तबका आदर्श साध्य के लिए घोर अनैतिकता के उपाय को सही साबित करने के काम पर लगा दिखे। तब भी इतिहास हमें यकीन दिलाता है कि नैतिकताशून्य स्थिति कभी नहीं आती। कन्हैया प्रकरण और खुद कन्हैया को सुनने के बाद क्या यह बात सही नहीं लगती...?

सुधीर जैन वरिष्ठ पत्रकार और अपराधशास्त्री हैं...

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) रू इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, ीव्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति टाइम्स ऑफ पीडिया उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार टाइम्स ऑफ पीडिया के नहीं हैं, तथा टाइम्स ऑफ पीडिया उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

Anti Assad protests erupt across Syria

Protesters also rejected all schemes to divide Syria and asserted the unity of their country and land. Since March 2011, Syrian opposi tion has been demanding an end to 44 years of rule of the Assad family in the country.

Damascus : Several cities in Syria erupted in protests against the Bashar al-Assad regime and Russia's aggression in the country Friday, Syrian activists told Anadolu Agency. The demonstrations also gave weight to reports that the Syrian revolution continues in the country despite the regime's atrocities.

According to Syrian activists, 22 protests took place in the provinces of Idlib, Aleppo, Homs, Daraa and Rif Dimashq, during which people demanded their rights to freedom and dignity. They condemned what they called Russian aggression and held banners demanding an end to sieges imposed by regime forces on Syrian cities; they also called for allowing immediate humanitarian and medical supplies into such areas. Protesters also rejected all "schemes to divide Syria" and asserted the unity of their country and land. Since March 2011, Syrian opposition has been demanding an end to 44 years of rule of the Assad family in the country.

The opposition is striving for a democratic state and devolution of powers. However, instead of listening to his people, the Assad regime has launched a military crackdown, which has resulted in a spate of violence and deadly battles between regime forces and opposition. Syria has remained locked in a vicious civil war since early 2011, when the Assad regime cracked down on pro-democracy protests with unexpected ferocity.

Since then, more than 250,000 people have been killed and more than 10 million displaced, according to UN figures.

—-Anadolu Agency

SUBSCRIPTION FORM
TIMES OF PEDIA

Issue	Subscription Price	Years
52	250/-	1
104	500/-	2
260	1,300/-	5
520	2,600/-	10
--	5,000/-	Life

Name :.....
Address :.....
.....
.....
Email:.....
Contact Phone No.....
for donation ☐ /life ☐ /10 yrs ☐/5 yrs☐subscription
The sum of Rupees..... (Rs...../-)
through cheque/DD No.....dt.....

Fill the above form neatly in capital letters and send it to us on the following address :
Times of Pedia, K-2-A-001, Abul Fazal Enclave-I,
Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025
or email : **timesofpedia@gmail.com**

Also Send us your subscription, membership, donation amount in favour of Times of Pedia, New Delhi
Punjab National Bank,Nanak Pura Branch,
New Delhi-110021
A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700

Ending Someone's thirst is the Biggest Deed of Humanity

ADVERTISEMENT TARIFF
TIMES OF PEDIA

Size/Insertion Single	B&W (Rs)	4 Colour (Rs)
Full Page (23.5 x 36.5 cm)	30,000/-	1,00,000/-
A4 (18.7 x 26.5 cm)	20,000/-	60,000/-
Half Page (Tall-11.6 x 36.5 cm)	18,000/-	50,000/-
Half Page (wide-23.5 x 18 cm)	8,000/-	50,000/-
Quarter Page (11.6 x 18 cm)	10,000/-	28,000/-
Visiting Card size (9.5 x 5.8 cm)	3,000/-	10,000/-

MECHANICAL DATA:

Language: English, Hindi and Urdu

Printing: Front and Back - 4 Colours , Inside pages - B&W

No. of Pages: 12 pages (more in future)

Price: Rs. 3/-

Print order: 25,000

Periodicity: Weekly

Material details: Positives/Format of your advertisements should reach us 10 days before printing.

Note: 50% extra for back page, 100% extra for front page

Please Add Rs. 10 for outstation cheques.

50% advance of total add cost would be highly appreciable, in case of one year continue add. Publication cost will reduce 50% of actual cost.

Bank transactions details of TIMES OF PEDIA
Send your subscriptions/memberships/donations etc. (Cheques/DD) in favour of TIMES OF PEDIA New Delhi
Punjab National Bank,Nanak Pura Branch , New Delhi-110021
A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700

समाचार पत्रों के आईने से

नूरसबा को इंसाफ नहीं मिला तो सड़क से संसद तक आंदोलनः वीमेन इंडिया मूवमेंट

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित शिक्षक एवं शिक्षाविद मसूद उमर खान की 73 वर्षीय विधवा नूरसबा का माननीय राष्ट्रपति द्वारा पूर्व भ्रष्ट विभिन्न न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारियों के विरूद्ध सीबीआई में मुकदमा पंजीकृत कराए जाने हेतु गृहसचिव भारत सरकार को राष्ट्रपति की संस्तुति भेजे जाने के बावजूद भ्रष्टाचार की जांच हेतु न्यायिक आयोग गठित करने से सम्बंधित न्यायिक विभाग भारत सरकार को माननीय राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए निर्देषों का अनुपालन नहीं हुआ। साथ ही नूरसबा की पेंशन आदि हकों के भुगतान के लिए वित मंत्री भारत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव को भेजे गए अनुरोध का पालन भी नहीं हुआ। जिससे दुखी होकर नूरसबा ने माननीय राष्ट्रपति और गर्वनर उत्तर प्रदेश द्वारा उनके पति को दिये गए उत्कृष सेवा पदक एवं पदमश्री सहित सभी राष्ट्रीय सम्मानों को राष्ट्रपति भवन पर जलाने का निर्णय किया है।

इस मौके पर विम की राष्ट्रीय अध्यक्षा यासमीन फारूकी ने कहा कि पिछले 36 सालो से अपने साथ होने वोले जुल्म व नाइंसाफी के साथ–साथ देश की तंत्र व्यवस्था से लड़कर आवाज उठाने वाली 73 वर्षीय बुजूर्ग महिला नूर सबा मंत्री से लेकर सन्त्री और राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खट–खटा चुकी हैं और आज तक इंसाफ के इंन्जार से पिछले कई महीनों से जन्तर मन्तर पर धरना दे रही है।

वीमेन इंडिया मूवमेंट (विम) ने एक बुजुर्ग महिला की बेबस आवाज को मजबती के साथ उठाने का प्रण किया है। विम का मामना है कि इन कृत्यो से न सिर्फ इंसानियत बल्कि कानून व संविधान दोनों आहत हुए हैं इंसाफ के रास्ते पर चलते हुए नूर सबा ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का जो रास्ता अपनाया है उस लड़ाई में 'विम' उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है कड़ाके की ठंड में 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला को खुले आसमान के नीचे राते बितानी पड़ी और आज तक यह संघर्ष जारी हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मानवाधिकार संगठन, अरविन्द केजरीवाल सभी जगह गुहार लगाई मगर कोई मदद को सामने नहीं आया है। वीमेंस इंडिया मूवमेंट भविष्य में किसी भी आम नागरिक के साथ ऐसा न हो इसके लिए नूर सबा की इस लड़ाई में उनके साथ है।

इस मौके नूर सबा ने अपने उत्पीड़न की कहानी सुनाने हुए कहा कि उनके पति मसूद उमर खां की नियुक्ति दिनांक 1.7.1959 को सीधे प्रधानाध्यापक के पद पर गवर्मेंट पब्लिक स्कूल रामपुर में

और मृत्यु सेवाकाल में 45 वर्ष की आयु में दिनांक 5.4.1980 को हुई शिक्षा जगत में उल्लेखनीय कार्यों के लिये उन्हें राष्ट्रपति एवं गवर्नर उ.प्र. द्वारा उत्कृष्ट सेवा पदक, दक्षता पुरस्कार, प्रशंसा पुरस्कार, वर्धी पब्लिक सर्वेट एवार्ड, पदमश्री सहित 5 प्रशस्ति पत्रों से नवाजा गया था। पति की मृत्यु के बाद शिक्षा विभाग द्वारा उत्पीड़न किया गया पति की मृत्यु (1980) के 36 साल बीत जाने के बाद रिश्वत न देने की वजह से शिक्षा विभाग उ. प्र. द्वारा उन्हें परिवारिक पेंशन ग्रैजुयेटी, फंड बीमा आदि हको से महरूम रखा। जिसका भुगतान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया गया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा पेंशन आदि हको से वंचित रखने के लिय शिक्षा विभाग द्वारा इनके पति की गवमेंट सर्विस से सम्बन्धित सारी सरकारी सेवा पत्रावलिया फाड़कर 1980 में गायब कर दी और उनकी जगह फर्जी सेवा पत्रावलियों की कूट रचना कर मेरे पति मसूद उमर खां को न सिर्फ एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल में बदला गया बल्कि पेंशन आदि के भुगतान फर्जीवाडे के रूप में इन फर्जी पत्रावलियों में दिखाये गये है। जिस षणयंत्र का परदाफाश उ.प्र. के राज्यपाल श्री विश्णुकान्त शास्त्री के आदेश पर उ.प्र. विजीलैस टीम द्वारा सन 2000 में जिला शिक्षा अधिकारी रामपुर के कार्यालय पर छापा मारकर असली व फर्जी दोनों रिकार्ड बरामद कर उन्हे हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में पेश किया लेकिन दोषियों पर कार्यवाही नहीं की गई।

इस मौके पर मौजूद विम की राष्ट्रीय कोषाध्यक्षा तराना शरफुद्दीन ने कहा कि यह लड़ाई एक ऐसी महिला की है जो पूरे सरकारी तंत्र से अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। इस लड़ाई में सालों गुजर जाने के बाद वे सिर्फ अपना हक ही नहीं चाहती बल्कि हमारी इच्छा है कि उन सभी लोगों को सजा मिले, जिन्होने नूर सबा के साथ अन्याय किया। अपने हक के लिए वे नेता–मंत्री से न्यायालय तक का दरवाजा खटखटा चुकी हैं लेकिन दुखद यह है कि इन सभी जगहों से न्याय मिलने की बजायें इन्हें सिर्फ नाउम्मीदी ही हासिल हुई है। प्रधानमंत्री से गुहार लगाने के बावजूद आज तक इंसाफ न मिलने के चलते इंसाफ की इस लड़ाई को वीमेन्स इंडिया मूवमेंट (विम) सड़क से संसद तक उठागी और एक बुजुर्ग महिला को इसांफ दिलाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने से भी पीछे नहीं रहेगी। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होने के लिए खास तौर से एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद व एडवोकेट असलम अहमद के साथ श्रीमती नूर सबा के बेटे उमर खान भी मौजूद थे।

Mehbooba Mufti meets governor

PDP, which was ruling the state in a coalition with the Bharatiya Janata Party, did not come forward to stake claim to form a new govt. A political stalemate between the PDP and the BJP over government formation in the state has been continuing for nearly two months now.

Jammu, March 4 : Peoples Democratic Party

(PDP) president Mehbooba Mufti on Friday met Jammu and Kashmir Governor N.N. Vohra here."PDP president Mehbooba Mufti called on Vohra at the Raj Bhawan and discussed the political and developmental scenario in the state with the governor," a PDP source told IANS.

The sources said Mufti had been invited for an informal meeting by the governor and she had called on him in response to that communication. The meeting lasted for more than an hour. Mufti told a membership rally of her party here earlier on Friday that her priority was strengthening of the party and not becoming the chief minister of the state.

Jammu and Kashmir was placed under governor's rule on January 8 after Chief Minister, Mufti Muhammad Sayeed passed away in New Delhi on January 7, and the PDP, which was ruling the state in a coalition with the Bharatiya Janata Party, did not come forward to stake claim to form a new government. A political stalemate between the PDP and the BJP over government formation in the state has been continuing for nearly two months now. Although both parties are saying their alliance is intact, there has been no forward movement to end the deadlock. It is generally believed here the PDP president wants firm assurances from the centre that the agenda of alliance between the two parties would be implemented in a time-bound manner. —IANS

AMU VC meets PM, tells centres not illegal

A delegation from AMU led by the Vice Chancellor, Lt. Gen. Zameer Uddin Shah calls on the Prime Minister, Shri Narendra Modi, in New Delhi on March 05, 2016.

New Delhi : AMU Vice Chancellor Lt. Gen. Zameer Uddin Shah (retd) met Prime Minister Narendra Modi on Saturday, and told him that the centres that the HRD ministry has called illegal were sanctioned by the president and government.

The vice-chancellor, who led a five member delegation, informed Modi about various research programmes going on in the Aligarh Muslim University including that on Ganga rejuvenation and agriculture technology.

He also told the prime minister that they have not been able to meet Human Resource Development Minister Smriti Irani despite several attempts, and have got an appointment for March 10, only the second meeting with her since she took charge.

"We told the prime minister that we are trying to meet the HRD minister since one and a half years, we could meet you twice, but with her, the first meeting was when she took charge, and the second meeting is scheduled for March 10," Shah told journalists after the meeting.

The AMU VC told the PM that the centres in Kerala, West Bengal and Bihar that the minister has called illegal have been sanctioned by the government only.

"The stand of HRD minister that the centres are illegal was explained. We told the prime minister that all bodies of AMU have been sanctioned by president of India and government of India, so how can they be illegal," he said.

He said they questioned the difference in allocations to the university vis a vis other universities like Jamia Millia Islamia (JMI) and Banaras Hindu University (BHU).

"We told him about the inequity of funds. Banaras Hindu University is the same as Aligarh Muslim University but they get Rs.100 crore more than us. Jamia Millia Islamia is half the size but it got Rs.689 crore more."

Shah said that they explained to the prime minister the ongoing programmes of the university which includes establishing modern education schools in Muslim majority areas."These will be secular schools, we don't want ghettoisation of education. The schools will have 50 percent Muslims and will be given modern education," he said.The VC also mentioned the bridge course being conducted by the university for Madrasa students to gear them up for modern education."These students are going to the Madrasas and telling them there is need for change," Shah said adding that religious education and modern education should go hand in hand.He also informed the prime minister about the research work in the university, which includes one on cleaning river Ganga, one of the pet projects of the NDA government."Our scientists are involved in the project Ganga. We told the prime minister that the research is low investment, there will be no need for electricity. We are also working on Swachh Bharat (Mission). There is a technique being developed where a car battery can be charged in 20 minutes, patrol and diesel will not be needed. We are doing research in agriculture on a nano fertiliser that will not pollute the soil," he said.Irani has maitained that the AMU off-campus centres have been established illegally and her ministry would not fund them.In a meeting with Kerala Chief Minister Oommen Chandy, she asked him to take back the land allotted to the AMU centre. —IANS

23 Maoists surrender in Chhattisgarh after killing 16

THE CHHATTISGARH Police claimed to have busted a local Maoist network created by "leaders from outside" in Kumakuleng area of Jagdalpur, with the surrender of 23 cadres. Three of the Maoists carried rewards of Rs one lakh each.Earlier at least 16 tribal villagers were shot dead allegedly by Maoists suspecting them to be police informers in different villages at red hotbed Narayanpur district of Bastar region on Tuesday and Wednesday.

Senior police officers said each of the surrendered Naxals had ration cards and Aadhaar cards. Most of them had election cards as well."The police have been working towards getting local Naxals to surrender to break the back of the Naxal organisation. We want that local Naxals surrender and work with the police against those from outside," a press statement issued by the police said. It added that the Maoist leadership allows locals to get official documents so that "they can take cover as poor villagers, adivasis or labourers".

It said things began to change after the death of Maoist commander Sonadhar, who was a "terror in the area". This led to a series of events that eventually led to the surrenders on Tuesday.

कन्हैया कुमार की हत्या का फरमान जारी

लखनऊ 5 मार्च 2016: रिहाई मंच अध्यक्ष मुहम्मद शुऐब ने जवाहरलाल नेहरु छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार से जेएनयू छात्रसंघ भवन नई दिल्ली में मुलाकात कर रोहित वेमुला के ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बधाई दी।

मंच ने कहा कि कन्हैया कुमार की हत्या का फरमान सुनाने वाले संघी गुण्डे ऐसी हरकतों से बाज आएं नहीं तो जिस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश भर में जनता ने संघियों को दौड़ा–दौड़ाकर पीटा था उसकी पुनरावृत्ति करने पर जनता को मजबूर होना पड़ेगा।

जेएनयू छात्र संघ भवन में कन्हैया कुमार से मुलाकात के बाद रिहाई मंच अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद शुऐब ने कहा कि कन्हैया कुमार को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद ही रिहाई मंच ने उन्हें सम्मानित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार ने उनसे कहा है कि जैसे ही उन्हें दिल्ली से बाहर निकलने का मौका मिलेगा वे लखनऊ आएंगे। इस अवसर पर मंच अध्यक्ष मुहम्मद शुऐब के साथ आजमगढ़ से जीतेन्द्र हरि पाण्डेय और पत्रकार प्रवीण सिंह मौजूद रहे।

रिहाई मंच अध्यक्ष ने कहा कि कन्हैया ने जिस तरह रोहित वेमुला के ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन को आगे बढ़ाने और एक शोषणविहीन समाज के लिए निणार्यक आंदोलन चलाने की बात की है उससे पूरा संघ परिवार डरा हुआ है। इसीलिए कन्हैया कुमार की हत्या के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के बदायूं जिलाअध्यक्ष कुलदीप वैष्णव बदायूं में तो वहीं दिल्ली में संघी गुंडा तत्व कन्हैया कुमार की हत्या के फरमान वाले पोस्टर चिपका रहे हैं।

मंच के अध्यक्ष मुहम्मद शुऐब ने राष्ट्रीय स्तर पर ब्राह्मणवाद–सांप्रदायिकता विरोधी इंसाफ पसंद नेताओं को आगामी 16 मार्च को लखनऊ में 'जन विकल्प मार्च' में शामिल होने की अपील की।

रिहाई मंच प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनिल यादव और शकील कुरैशी ने कन्हैया कुमार की जीभ काटने और हत्या जैसे फरमान सुनाने वाले पूर्वांचल सेना और भाजयुमो की हरकत को मोदी सरकार में अराजक तत्वों को मिली खुली छूट का ताजा उदाहरण बताया है। मंच ने मांग की कि भाजयुमो बदायूं जिला अध्यक्ष कुलदीप वैष्णव पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करे अखिलेश सरकार।

जिन लोगों ने पीएम मोदी के लिए वोट दिया वे अब रिफंड चाहते हैं: राहुल गांधी

बोरघाट (असम): केंद्र पर दबाव बनाते हुए राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि ईपीएफ पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव वापस लेने तक वह अपना संघर्ष जारी रखेंगे। असम में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री ने हाल में अपनी बजट की फेयर एंड लवलीश योजना में चोरों को काले धन को सफेद करने का अवसर दिया है, लेकिन ईमानदारी से वेतन कमाने वाले वर्ग के जीवन भर की संचय निधि पर कर लगा दिया है।

प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए राहुल ने उन पर चुनावी वादे पूरा नहीं कर लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया और कहा कि जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया वे अब रिफंड चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं इस सरकार पर दबाव बनाना जारी रखूंगा क्योंकि यह ईमानदार कामगार वर्ग की सरकार नहीं है... यह गरीब किसानों, पिछड़े वर्ग, युवकों, महिलाओं, दलितों, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की सरकार नहीं है।

राहुल ने कहा कि वह वेतनभोगी वर्ग के लिए लड़ते रहेंगे और सरकार पर दबाव बनाए रहेंगे जो उद्योगपतियों के एक चुनिंदा समूह और काला धन रखने वालों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा, मैंने मीडिया में कहा और प्रधानमंत्री से भी कहा था कि उनकी ईमानदार संचयन निधि पर कर नहीं लगाएं और इस बारे में कुछ करें। लेकिन बृहस्पतिवार को संसद में अपने एक घंटे के भाषण में इस बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016–17 के बजट में इस वर्ष 1 अप्रैल के बाद ईपीएफ निकासी पर 60 फीसदी कर लगाने का प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव का विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों और अन्य वर्गों ने विरोध किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राज्य के दो–दिवसीय दौरे पर हैं और इससे पहले उन्होंने नौगांव से बोरघाट तक छह किलोमीटर की पदयात्रा की।

NDTV

वादा किया था, वादा निभाओ खेती और किसान बचाओ

भारतीय किसान संघ का 38वां स्थापना दिवस आज धूमधाम से गुरू महाराज जी की बगीची मुहाना ग्राम में भारतीय किसान संघ की सांगानेर तहसील ईकाई की ओर से मनाया गया आज ही के दिन महान विचारक चिन्तक श्रद्धेय श्री दन्तोपन्त ठेगडी जी 4 मार्च 1979 को पूरे भारतवर्ष के 6 लाख गॉव में भ्रमण कर और किसानों की पीडाओं को समझकर 650 समस्त भारतीय ग्राम प्रतिनिधियों के साथ मंथन एवं चिंतन कर राजस्थान के कोटा में भारतीय किसान संघ की स्थापना की थी।

आज पूरे भारतवर्ष के 500 ग्रामों में लगभग 30 लाख कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय किसान संघ किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक वटवृक्ष की भांति उनको संरक्षण देता हुआ खडा है अभी पिछले माह में 19,20,21, फरवरी 2016 को ही भारतीय किसान संघ का 11वां अखिल भारतीय अधिवेशन मुहाना मण्डी में सम्पन्न हुआ है। जिसमें देशभर से आये हुये विभिन्न जिलों से आये हुये लगभग 7000 किसान प्रतिनिधियों ने केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से प्रत्येक ग्राम इकाई से 15 मार्च 2016 तक अखिल भारतीय किसान संघ के अधिवेशन में पारित प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही करवाने के लिए प्रत्येक ग्राम ईकाई से हस्ताक्षरयुक्त प्रस्ताव की प्रतियां माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार तथा महामहीम राष्ट्रपति जी भारत सरकार तक प्रेषित करने का निर्णय लिया है।

गुरूमहाराज जी की बगीची में पूर्णतया उत्सव का माहौल था तथा सभी 63 ग्राम ईकाईयों व 30 पंचायतो के प्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सोहन जी शर्मा मुहाना ने की विशिष्ट अतिथि प्रान्तीय महामंत्री जगदीश जी तथा मुख्य अतिथि मंजू दिक्षित व कार्यक्रम संयोजक छोटे लाल जी सैनी ने लगभग 300 ग्राम इकाई कार्यकर्ताओं के समक्ष विचार व्यक्त किये एवं कार्यक्रम का समापन भोजनप्रसादी के साथ किया।

(राजीव दीक्षित)
प्रचार प्रमुख भा.कि.स.
मो0 – 9414044596

छत्तीसगढ़: रायपुर में उपद्रवियों ने चर्च में की तोड़फोड़, लोगों की पिटाई भी की

रायपुरः रायपुर शहर के बाहरी हिस्से में कचना गांव में 15 से 20 युवकों के एक समूह ने एक चर्च में घुसकर परिसर में कथित तौर पर तोड़–फोड़ की और वहां मौजूद लोगों को पीटा।

रायपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर ने कहा, तकरीबन 15 से 20 युवक उस वक्त कचना गांव में स्थित चर्च परिसर में घुस गए, जब वहां प्रार्थना चल रही थी। चंद्राकर ने

कहा कि उन्होंने परिसर में कुर्सियां, पंखे और अन्य वस्तुओं को क्षति पहुंचाई और वहां मौजूद लोगों की पिटाई भी की।

एएसपी ने बताया कि आरोपियों ने अपने माथे पर कथित तौर पर भगवा पट्टी बांध रखी थी। पुलिस के पहुंचने पर वे घटनास्थल से भाग गए। उन्होंने बताया कि पीड़ितों की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 452 (चोट पहुंचाने की तैयारी के बाद घर में अनधिकार प्रवेश), धारा 295 (किसी वर्ग के धर्म को अपमानित करने की मंशा से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाने या विरूपित करना) और धारा 147 (दंगा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा कि आरोपियों की तीन मोटरसाइकिलों को घटनास्थल से जब्त कर लिया गया है। उपद्रवियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। ndtv

टाइम्स ऑफ़ पीडिया
TIMES OF PEDIA
ٹائمس آف پیڈیا
NEW DELHI Page 12 Price ₹ 3.00
अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इंसाफ़ की डगर पर
www.timesofpedia.com
WEEKLY HINDI ENGLISH URDU
WED 02 MAR - TUE 08 MAR 2016 VOL. 4 Issue 18 RNI No. DELMUL/2012/47011 P.Reg. No. DL(S) - 01/3431/2013 - 15

بھارتی سکیورٹی پر اعتماد، پاکستانی ٹیم بھارت جانے کے لیے تیار

حکومتِ پاکستان نے کرکٹ کے ورلڈ ٹی20 مقابلوں میں شرکت کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کو بھارت جانے کی اجازت دے دی ہے۔

پاکستان کی وزاتِ داخلہ کی جانب سے جمعے کی شام جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ مغربی بنگال کی وزیرِ اعلیٰ، کولکتہ کی پولیس کے سربراہ اور خصوصاً بھارتی وزیرِ داخلہ کی جانب سے پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط کو کروائی جانے والی یقین دہانیوں کے بعد کیا گیا ہے۔

اس سے قبل وزیرِ داخلہ چوہدری نثار علی خان سے ملاقات کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایگزیکیٹیو کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے بتایا تھا کہ حکومتِ پاکستان کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد اب ٹیم پہلی دستیاب پرواز سے آج شب یا کل صبح دبئی کے راستے بھارت روانہ ہو جائے گی۔ ٹیم کو بھارت بھیجنے کے معاملے پر وزیرِ داخلہ چوہدری نثار علی خان نے جمعے کو ہی سعودی عرب میں موجود وزیرِ اعظم پاکستان اور لاہور میں چیئرمین پی سی بی شہریار خان سے بھی رابطے کیے تھے۔ اس کے علاوہ دہلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط نے ٹیم کی سکیورٹی کے معاملے پر بھارتی سیکریٹری داخلہ سے ملاقات کے بعد کہا تھا کہ ملاقات مثبت رہی ہے اور وہ اپنی سفارشات حکومتِ پاکستان کو بھجوا رہے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ بھارتی سیکریٹری داخلہ نے پاکستانی کرکٹ ٹیموں کے تحفظ کی یقین دہانی کروائی ہے اور کہا ہے کہ 'ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کا میچ ہو'۔ خیال رہے کہ جمعرات کی شام وزیرِ داخلہ چوہدری نثار علی خان نے کہا تھا کہ 'ہر پاکستانی شہری اور حکومت چاہتی ہے کہ پاکستانی ٹیم بھارت جائے لیکن اگر حکومتی سطح پر ضمانت نہ دی گئی تو پاکستانی ٹیم کو بھارت جانے کی قطعی اجازت نہیں دی جائے گی'۔

ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 'کرکٹ دھمکیوں کے سائے میں کیسے ہو سکتی ہے اور ہم صرف 'لیول پلیئنگ فیلڈ' مانگ رہے ہیں'۔

پاکستان کے وزیرِ داخلہ کے بیان کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری انوراگ ٹھاکر نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ٹیم بھی دیگر ٹیموں جتنی ہی اہم ہے اور کسی ٹیم کو ٹورنامنٹ میں حصہ نہ لینے کے لیے کوئی بھی بہانہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ 'اس معاملے پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے۔۔۔ کسی کو ٹورنامنٹ میں حصہ نہ لینے کے لیے کوئی بھی بہانہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے اور پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ناقص پرفارمنس پر دھیان دے نہ کہ سیاست کرنے پر'۔

''تہاڑ جیل، نئی دہلی کے صدرِ دفتر میں ''سرو شانتی ست سنگ'' کا انعقاد

حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد حنیف شاستری، ایڈوکیٹ مکرند دینا نیشوراڈکر اور مولانا محمد اعجاز الرحمٰن شاہین قاسمی

ورلڈ پیس آرگنائزیشن، نئی دہلی کی جانب سے تہاڑ جیل، نئی دہلی کے صدر دفتر میں ''سرو شانتی ست سنگ'' منعقد کیا گیا۔ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ این جی او مسٹر سنجے کمار امباستا کے تعارفی کلمات سے پروگرام آغاز ہوا۔ اس موقع پر راشٹریہ سنسکرت سنستھان اور ورلڈ پیس آرگنائزیشن کے رکن پروفیسر ڈاکٹر محمد حنیف خان شاستری نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک کوئی نئی آسمانی کتاب نہیں ہے۔

اس سے پہلے بھی دیگر پیغمبروں پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور قرآن کریم سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ انہوں نے قرآن پاک، وید اور گیتا کے حوالے سے اس کو ثابت کیا اور کہا کہ ہر جگہ ہمیں سچائی ملی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہنے والا ایک ہے۔ اس لئے ہم کو اس ایک مالک یعنی اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنا چاہیے۔ ڈاکٹر محمد حنیف خان شاستری نے کہا کہ ہندو، مسلمان اور دیگر مذاہب میں بھی جنت اور دوزخ کا تصور موجود ہے جو لوگ اچھے کام کریں گے اور نیک راستے پر زندگی بسر کریں گے انہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے اور جو لوگ بُرے اور شیطان کے راہ پر چلیں گے انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

ورلڈ پیس آرگنائزیشن، نئی دہلی کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد اعجاز الرحمٰن شاہین قاسمی نے کہا کہ تہاڑ جیل کے اانتظامیہ کے درمیان پروگرام منعقد کر کے ہمیں بے حد خوشی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیل انتظ ؟امیہ کے ایک پولس کی نگرانی میں سیکڑوں قیدی ہوتے ہیں اور یہ لوگ قیدیوں کی خدمت میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کسی ''سرو شانتی ست سنگ'' جیسے اصلاحی پروگراموں میں شرکت کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اس لئے ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی ذہنی، قلبی اور روحانی تسکین کے لئے ''سرو شانتی ست سنگ'' اور ڈسکشن پروگرام منعقد کریں تا کہ انہیں قلبی اور روحانی تسکین مل ہو سکے اور ان کے اندر بلا تفریق مذہب وملت اخلاص کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو سکے۔

ورلڈ پیس آرگنائزیشن، نئی دہلی کے رکن اور سپریم کورٹ کے وکیل جناب مکرند دینا نیشوراڈکر نے کہا کہ آپ کیلئے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ لوگ قیدیوں کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ۔ آپ لوگ قیدیوں کے اخلاق وعادات کو سدھارنے اور نیک راستے پر لانے کیلئے تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی پروگرام جو منعقد کرتے ہیں یہ بہت عمدہ اور اچھا کام ہے۔ میں آپ کو مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ قیدیوں کو آپ جیسے مخلص اور ہمدرد افسران کی خدمات انہیں حاصل ہیں۔ ان کے لئے یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس موقع پر شرکاء نے کئی سوالات کئے جس کا مثبت اور معقول جواب دیا پیش کیا گیا۔ ''سرو شانتی ست سنگ'' پروگرام میں ایچ کے شرما، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ این جی او مسٹر سنجے کمار امباستا، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ایچ کے شرما اور جیل انتظامیہ دیگر افسران وکارکنان کے علاوہ مولانا محمد اعجاز الرحمان شاہین قاسمی، ڈاکٹر حنیف خان شاستری، مولانا دلشاد قاسمی، محمد نعیم وغیرہ کا نام قابل ذکر ہیں۔

کیپشن:

میڈیا سیل

ورلڈ پیس آرگنائزیشن، نئی دہلی